भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1302

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

1302. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की संख्या और उनके परिमाण के बारे में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी विभाग-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने प्रत्येक ऐसी योजना से सृजित होने वाली नौकरियों की संख्या का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार देश में ऐसी और अधिक पीएलआई योजनाएं शुरू करना चाहती है, यदि हां, तो इसके लिए कार्य योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार के पास देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में ऐसी योजनाओं के प्रभाव के बारे में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्युटिकल औषधियां, (vi) विशिष्ट इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी) (x) खाद्य सामग्री, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने की क़िफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है।

सभी 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीम संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद अधिसूचित की गई हैं। ये स्कीमों कार्यान्वयनकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को जोड़ने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पीएलआई स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों को राष्ट्रीय लक्ष्यों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र आदि में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक रूप से चुना गया है ताकि उनकी मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

अगस्त, 2024 तक, सभी 14 क्षेत्रों में 1.46 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 9.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुआ है। पीएलआई स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान से निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उदाहरण के लिए, पीएलआई स्कीम की शुरुआत के बाद मोबाइल फोन का निर्यात दो गुना से ज्यादा बढ़ गया है और भारत में महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स जैसे बायो-फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक, ऑफन ड्रग्स, कैंसर रोधी दवाओं आदि के उत्पादन के लिए क्षमता विकसित की गई है।